

प्रेस विज्ञप्ति

दिल्ली जल बोर्ड की 179वीं बोर्ड बैठक में जल एवं सीवर ढांचे के विस्तार और यमुना पुनर्जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंथन

नई दिल्ली, 28 जुलाई 2026:

दिल्ली सचिवालय में माननीय जल मंत्री एवं दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रवेश साहिब सिंह की अध्यक्षता में दिल्ली जल बोर्ड की 179वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई।

बैठक में दिल्ली जल बोर्ड के माननीय उपाध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिन्होंने दिल्ली में जल एवं सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने तथा नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बोर्ड की प्रतिबद्धता को और सशक्त किया। बैठक में दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) श्री सज्जन सिंह यादव भी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य श्री अजय महावर, श्री मनोज शौकीन एवं श्री राजेश गोयल भी बैठक में उपस्थित रहे।

दिल्ली जल बोर्ड के इतिहास में पहली बार किसी एक बोर्ड बैठक में 50 एजेंडा प्रस्तुत किए गए। इनमें 2 प्रक्रियात्मक, 13 प्रशासनिक और 35 तकनीकी एजेंडा शामिल थे। बैठक में यमुना पुनर्जीवन, सीवेज ट्रीटमेंट, जल एवं सीवर नेटवर्क के विस्तार, उपभोक्ता सेवाओं और राजस्व व्यवस्था को बेहतर बनाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

यमुना पुनर्जीवन एवं सीवेज ट्रीटमेंट

दिल्ली जल बोर्ड यमुना में बिना उपचारित सीवेज के प्रवाह को रोकने, सीवेज शोधन क्षमता बढ़ाने तथा नदी के समग्र पुनर्जीवन के लिए चरणबद्ध रूप से व्यापक परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। इसी दिशा में बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई, जो स्वच्छ यमुना और बेहतर शहरी जल प्रबंधन के लक्ष्य को गति देंगी।

दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 15 डीएसटीपी के निर्माण के लिए ₹1,947.89 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इन परियोजनाओं से 176 कॉलोनियाँ और 53 गांवों की आबादी लाभान्वित होगी।

इसके साथ ही मौजूदा 7 एसटीपी के अपग्रेडेशन के लिए ₹525.99 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। ड्रेन गैप एनालिसिस के आधार पर 13 नए एसटीपी के निर्माण के लिए ₹7,373 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया। इन परियोजनाओं को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के माध्यम से पूरा करने की योजना है।

इसके अतिरिक्त, 10 एसटीपी में आधुनिक स्लज मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित करने के लिए ₹274.20 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इससे स्लज का वैज्ञानिक निस्तारण सुनिश्चित होने के साथ बिजली और हरित ऊर्जा के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा।

दिल्ली गेट ड्रेन में गिरने वाले 50 से 80 एमजीडी गंदे पानी के मौके पर ही ट्रीटमेंट के लिए तीन वर्ष की अवधि और ₹65.74 करोड़ की अनुमानित लागत वाली परियोजना को अवॉर्ड करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

लगभग ₹1,601 करोड़ के नौ सीवर नेटवर्क

बैठक में लगभग ₹1,601 करोड़ की संयुक्त लागत वाले नौ सीवर नेटवर्क को अवॉर्ड करने से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इन परियोजनाओं से 229 कॉलोनियाँ और 55 गांवों में सीवर नेटवर्क का विस्तार होगा।

इन कार्यों में किराड़ी, बाजितपुर ठाकरान-औचंदी, पल्ला-खेड़ा खुर्द, छतरपुर एक्सटेंशन, जौनापुर, महिपालपुर, ताजपुर पहाड़ी, टिकरी कलां, ताजपुर खुर्द, मोहम्मदपुर माजरी-कंझावला तथा नरेला क्षेत्र के आठ गांवों में सीवर नेटवर्क और हाउस सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराना शामिल है।

जिंदपुर की 14 कॉलोनियों में हाउस सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराने और रोहिणी सेक्टर-20 से 25 तक ट्रंक सीवर के पुनर्वास के लिए लगभग ₹140 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर

भगीरथी, द्वारका और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन, रखरखाव एवं आवश्यक पुनर्वास से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

संगम विहार में **4.8 एमजी क्षमता का भूमिगत जलाशय (UGR) ₹193.26 करोड़** तथा तुगलकाबाद में **1.2 एमजी क्षमता का UGR ₹48.31 करोड़** की लागत से बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इनसे संबंधित क्षेत्रों में जल भंडारण क्षमता, प्रेशर और जलापूर्ति व्यवस्था बेहतर होगी।

सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए **₹58.94 करोड़ की अनुमानित लागत से 250 वाटर एटीएम** लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

लगभग 29.7 लाख उपभोक्ताओं की E-KYC

दिल्ली जल बोर्ड के लगभग **29.7 लाख उपभोक्ताओं** की घर-घर ई-केवाईसी, मीटर रीडिंग और बिल वितरण के लिए **₹49 करोड़** का प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इसे तीन क्लस्टर में लागू करने की योजना है। रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 के संचालन एवं रखरखाव के लिए **₹4.45 करोड़** की राशि का विस्तार किया गया।

प्रशासनिक एवं संस्थागत सुधार

दिल्ली जल बोर्ड की प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करने के लिए लगभग **₹33.70 करोड़ के वार्षिक व्यय से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर 700 प्रशासनिक कार्मिकों** की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा, **यंग एक्वा लीडर्स इंटरनशिप प्रोग्राम** के अंतर्गत 40 विद्यार्थियों को अवसर देने की स्वीकृति दी गई।

बैठक में स्वीकृत समस्त कार्य दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता बढ़ाने, यमुना में बिना ट्रीटमेंट के गिरने वाले गंदे पानी को रोकने, जलापूर्ति एवं सीवर नेटवर्क को मजबूत करने और उपभोक्ता सेवाओं को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।